भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4915

1 अप्रैल, 2025 को उत्तर के लिए

इस्पात निर्यात और टैरिफ

4915. श्री गुरमीत सिंह मीत हायेर:

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों में भारत से अमेरिका को निर्यात किए गए इस्पात की कुल मात्रा का ब्यौरा क्या है और मूल्य के वर्षवार आंकड़े क्या हैं;

(ख) अमेरिका द्वारा हाल ही में लगाए गए टैरिफ से भारत के इस्पात निर्यात पर क्या असर पड़ा है और इस प्रभाव को कम करने के लिए कौन से वैकल्पिक बाज़ारों की तलाश की जा रही है;

(ग) निर्यात में विविधता लाने तथा वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने के लिए भारतीय इस्पात निर्यातकों को सहायता प्रदान करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने टैरिफ कटौती या छूट के संबंध में अमेरिका के साथ कोई चर्चा की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या प्रगति हुई है; और

(ङ) क्या भारतीय इस्पात उद्योग के लिए बदलती वैश्विक मांग और स्थिरता आवश्यकताओं के अनुरूप दीर्घकालिक रणनीति बनाई गई है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)**

(क): विगत पाँच वर्षों में भारत से संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात किए गए तैयार इस्पात की कुल मात्रा तथा मूल्य का वर्ष-वार विवरण निम्नानुसार है:-

यूएसए को तैयार इस्पात का निर्यात		
वर्ष	**मात्रा('000 टन में)**	**मूल्य (करोड़ रू. में)**
2019-20	51	571
2020-21	27	435
2021-22	214	2,621
2022-23	165	3,177
2023-24	95	1,924
स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी)		

(ख) से (ङ): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और इसका आयात तथा निर्यात मांग एवं आपूर्ति, बाजार की शक्तियों संबंधी गतिशीलता द्वारा निर्धारित होता है। सरकार देश में इस्पात क्षेत्र के विकास हेतु अनुकूल वातावरण सृजित कर एक सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करती है।

जारी...2/-

संयुक्त राज्य अमेरिका ने वैश्विक आधार पर मार्च, 2018 में व्यापार विस्तार अधिनियम, 1962 की धारा 232 के तहत इस्पात पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। भारत सरकार पारस्परिक रूप से लाभकारी और निष्पक्ष तरीके से द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को बढ़ाने और उन्हें व्यापक बनाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के साथ लगातार बातचीत जारी रखे हुए है। दोनों देशों ने दिनांक 13 फरवरी, 2025 को एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया, जिसमें आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई। महत्वाकांक्षी "मिशन 500" के तहत, दोनों देशों का लक्ष्य वर्ष 2030 तक अमेरिकी-भारत व्यापार को दोगुने से अधिक करके 500 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंचाना है, जिसे इस्पात सहित कई क्षेत्रों में व्यापार संबंधों को मजबूत करके हासिल किया जाएगा।

*****